ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4
ऑनलाइन पढाई जरूरी नहीं मजबूरी है

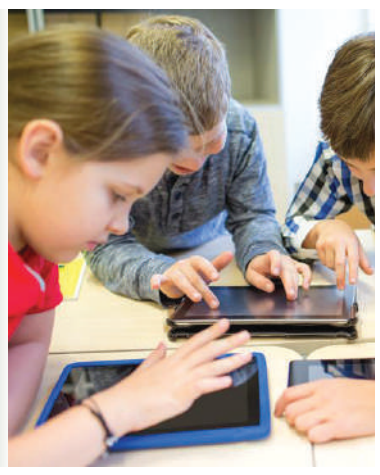

रविवारीय, 03-09 मई 2020 वर्ष- एक, अंक-39, रांची, कुल पृष्ठ 4 | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 | www.greenrevolt.news | मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

शालीमार -रांची- शालीमार विशेष पार्सल ट्रेन का परिचालन अब 15 मई तक

ट्रेन संख्या 00801/ 00802 शालीमार -रांची -शालीमार विशेष पार्सल ट्रेन का परिचालन दिनांक 15 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। संपूर्ण देश में लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा 9 अप्रैल से यह ट्रेन प्रारंभ की गई थी । उपरोक्त पार्सल ट्रेन चलाने से किसानों एवं सब्जी व्यवसायियों को लॉक डाउन के दौरान अपने उत्पादों को विभिन्न जगह तक पहुंचाना आसान हो गया है। इस विशेष पार्सल ट्रेन से कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु उपयोग में आने वाले उपकरण, मास्क, पीपीई किट्स आदि सामान भी रांची मंगाने में सहायता हो रही है ।

लॉकडाउन में बाहर से लौटे राज्य के मजदूरों को झारखंड में हीं काम देने को प्रयासरत हैं मुख्यमंत्री पर

क्या सरकार दे पायेगी रोजगार?

मुख्य संवाददाता

रांची : लॉकडाउन में झारखंड से बाहर गये मजदूर भाग-भाग कर राज्य में वापस आ रहे हैं। वहां उनके भूखे मरने की नौबत आ गयी थी। ऐसे में वो किसी भी तरह से अपने गांव और कस्बों की ओर लौटना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्र सरकार की पहल पर राज्य में मजदूरों की वापसी संभव हो रही है, ट्रेनों से मजदूरों का आना शुरू हो गया है। ऐसी ही हालत बिहार , यूपी और बंगाल जैसे राज्यों की भी है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा से पांच करोड़ से भी ज्यादा मजदूर पलायन कर देश के महानगरों में काम करते हैं। और इनमें से ज्यादतर की स्थिति बहुत बुरी है। महानगरों में इनका कोई स्थायी ठौर ठिकाना और आर्थिक सुरक्षा न के बराबर है।

लॉकडाउन से बेरोजगार हुये झारखंड के मजदूर राज्य में वापस तो आ रहे हैं लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनमें से जो कामगार और मजदूर वापस नहीं जाना चाहते उन्हें राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाये। हालांकि मुख्यमंत्री इन्हें रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं, पर झारखंड में पलायन रोकने और राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने का दावा दशकों से सिर्फ शिगुफा ही साबित होते आया है। पिछली सरकार ने हजारो की संख्या में नौकरी बांटने का दावा कर अपनी पीठ थपथपाने का काम किया, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें महानगरों में नौकरी बहुत कम सैलरी में मिली जो स्किल्ड होकर घर से दूर महानगरों में रहने के लिये पर्याप्त नहीं थे। आज भी हम रांची , हटिया रेलवे स्टेशन से जब महानगरों के लिये ट्रेनें खुलती हैं तो उसमें सैकड़ो झारखंडी मजदूरों को सवार होते देख सकते हैं। इनमें मुबंई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरू जैसे महानगरों में काम के लिये जाने वाले युवा दिख जायेंगे।

झारखंड पर पहले से ही है पलायन और मानव तस्करी का दाग

राज्य से लाखो लड़कियां दिल्ली , मुबंई जैसे महानगरों में जाकर काम करती हैं जहां उनका शोषण होता है, झारखंड इस मायने में शर्मनाक तरीके से कुख्यात है कि यहां राष्ट्रीय स्तर के मानव तस्कर हैं जो झारखंड के युवक युवतियों को महानगरों में शोषण के जाल में फंसाते रहे हैं, इन मानव तस्करों का उठना बैठना दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्रियों तक के साथ है।

हालांकि राज्य से बाहर गये सभी मजदूर या युवक युवतियों का शोषण ही होता हो ऐसा नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में काम करने वाले युवक युवतियों, मजदूरों के भेजे पैसों से राज्य के उन इलाकों में लोगों का जीवन स्तर सुधरा भी है जहां राज्य सरकारें अब तक कुछ नहीं कर पायीं हैं। लेकिन इस तथ्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि दो दशक पहले बने राज्य में कोई भी सरकार राज्य का इतना विकास नहीं कर पायी कि यहां से पलायन रूके। झारखंड से हर साल लाखो लोग काम के लिये पलायन कर बाहर जाते ही हैं उनमें सभी अपनी इच्छा से नहीं जाते और ज्यादतर बाहर में शोषण का शिकार होते हैं।

बिना सरकारी मदद के लौटे हैं लाखो मजदूर

सरकार भले ट्रेन या प्लेन तक से बाहर फंसे मजदूरों को राज्य में लाने का दावा कर रही है पर इसके माध्यम से वह लाखो मजदूरों को वापस नहीं ला सकती। और न ही अब तक बाहर फंसे सभी मजदूरों ने सरकारी मदद का इंतजार किया है। लाखो रूपये में भाड़े पर बस करके महाराष्ट्र , गुजरात से मजदूर अपने घर वापस लौटे हैं, वहीं हजारो रूपये देकर टैक्सी से मुंबई तक से भाग कर लोग झारखंड के अपने गावों में आये हैं। देखने वालों ने खुद ग्रीन रिवोल्ट को बताया है कि कुछ समय से उनके गांवों में महाराष्ट्र गुजरात के नंबरों वाली टैक्सी की दिखने लगी है और अच्छी रकम देकर आये कामगार स्थिति समान्य होते ही इनमें से ज्यादतर वापस महानगरों का ही रूख करेंगे।

कैसे जगेगा भरोसा?

कुछ महिने पहले संथाल क्षेत्र के एक युवक के परिजन की भूख से मौत हो गयी। युवक गुजरात में मजदूरी करता था, वहां उसने अपने मालिक से झारखंड जाने की बात कह मजदूरी की मांग की तो उसके मालिक ने सिर्फ भाड़ा देकर भगा दिया। और युवक जब अपने गांव पहुंचा तो उसके जेब में किसी तरह बचा कर रखे गये मात्र पचास रूपये थे।

राज्य में हर साल भूख से मरने की खबरें आती हैं और सरकार किसी की भी हो वह उस खबर की लीपापोती में लग जाती है। भले मुख्यमंत्री वापस आये मजदूरों कामगारों को यहीं काम देने का वादा कर रहे हैं पर वर्तमान सरकार ने स्मार्टरोड बनाने के तकरीबन सभी कार्यों को रद्द कर दिया है, निर्माण या रोजगारपरक किसी काम में सरकार कदम नहीं बढा रही। राज्य के कई जिलों के सुदूर इलाकों में ऐसी स्थिति है कि वहां किसी भी सरकारी मदद की पहुंच पर संशय है उनकी मोनिटरिंग करने वाला कोई नहीं। कोरोना संकट में भी गरीबों का राशन तक ठिक से नहीं बंट रहा है, सरकार ने दर्जनों राशन डीलरों का गबन के आरोप में लायसेंस रद्द किया है और इसमें बड़े अधिकारियों तक के संलिप्तता के आरोप लगते रहे हैं।

ऐसा भी देखने को मिला है कि किसी योजना के तहत स्किल्ड कर युवक युवतियों को बहुत कम सैलरी पर महानगरों में काम दिलाया गया उनका कहना था कि वो अपने गांव में महुआ चुन कर ज्यादा उनमुक्त और खुश थे, यहां तो उन्हें पांच दस हजार में देकर गुलामों सा काम कराया जाता है। वहीं जो झारखंडी युवा बाहर अच्छी कमाई कर रहे थे, वो यहां काम मिलने पर वैसी ही आमदनी चाहेंगे ऐसा नहीं होने पर ये बगैर कोई शिकायत किये स्थिति सुधरते ही महानगरों का रूख करेंगे ही।

आम दिनों में भी अच्छे से हाथ धोने की आदत बनायें

मनोरंजन सिंह

बीमारियों से बचाव और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे (विश्व हाथ स्वच्छता दिवस) के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में जब सारा विश्व कोरोना संक्रमण के संकट से त्राहीमाम है ऐसे में हाथों की साफ सफाई का महत्व और बढ जाता है। हर रोज यह बात बतायी जा रही है कि कोविड 19 वायरस को मारने के लिये कम से कम हमें 20 सेकेंड तक साबुन या डिटर्जेंट से हाथ धोने की जरूरत है। और ज्यादतर लोग अभी कोरोना के भय से हाथ धोने पर विशेष ध्यान दे भी रहे हैं इस कारण से सेनेटाइजर और हैंड वाश की मांग भी बढ गयी है। लेकिन ये आदत अगर कोरोना संकट के खत्म होने के बाद भी बनी रहे तो देश के स्वास्थ्य के लिये बहुत हितकर होगा।

विश्व हाथ स्वच्छता दिवस

कोरोना संकट को अगर हम छोड़ दें तो भी आम दिनों में हाथों की ठीक से सफाई न रखने और गंदे हाथों से खाने-पीने से सबसे ज्यादा डायरिया का खतरा होता है। 2018 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण डायरिया है। आमतौर पर बच्चे हाथ धोने को लेकर ज्यादा संजीदा नहीं होते। ऐसे में पेरेंट्स को ही हाथ धोने पर जोर देना चाहिए। खेलने के बाद जब भी बच्चे घर आएं, तो बिना अच्छी तरह से हाथों को धोए कुछ भी खाने ना दें। बच्चों में सही तरीके से हाथ धोने की आदत विकसित करें।

हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोने पर बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर, उन लोगों को ये बीमारियां जल्दी प्रभावित करती हैं, जिनकी इम्यूनिटी क्षमता कमजोर होती है। टॉयलेट से आने के बाद और खाने से पहले आप कितनी देर आत धोते हैं? यदि 5 या 10 सेकंड ही हाथ धोते हैं वह भी सिर्फ पानी से तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि 10 सेकंड हाथ पानी, साबुन से धो लिया तो काफी है, पर इससे हाथों में मौजूद कीटाणु मरते नहीं हैं। आज भी बहुत से लोग हैं, जो हाथों को साबुन से साफ करना जरूरी नहीं समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ के सिर्फ एक वर्ग सेन्टीमीटर के हिस्से में 1500 से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जो आपको बीमार बना सकते हैं। ये कीटाणु कई गंभीर बीमारियों का शिकार बनाते हैं। उन लोगों को ये बीमारियां जल्दी प्रभावित करती हैं, जिनकी इम्यूनिटी क्षमता कमजोर होती है। जब आप गंदे हाथों से अपनी आंखों, नाक और त्वचा को छूते रहते हैं, तो इनके जरिए हाथों के कीटाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ये ही कीटाणु संक्रमण का कारण बनते हैं। हर 3 घंटे में कम से कम एक बार अपना हाथ जरूर धोएं। गंदी वस्तुओं के छूने के बाद तो हाथ धोना बेहद जरूरी है वरना संक्रमण तेजी से फैलने लगता है।

लॉकडाउन में उर्वरकों की बिक्री 32 प्रतिशत बढ़ गयी

राजेश कुमार

कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच उर्वरकों की बिक्री में 32 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल, 2020 के बीच 10.63 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री हुई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 8.02 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है।

केंद्रीय रसायन मंत्रालय के अनुसार 1 से 22 अप्रैल के दौरान डीलरों ने 15.77 लाख मीट्रिक टन उर्वरक खरीदे, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में खरीदे गए 10.79 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवागमन पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध होने के बावजूद उर्वरक विभाग रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों से देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति बिना किसी रुकावट के कर रहा है। यह किसानों को आगामी खरीफ फसल के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकारों के पास उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सदानंद गौड़ा ने यह भी

कहा है कि उनका मंत्रालय किसानों के लिए बुआई से पहले उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने बताया कि 17 अप्रैल को 41 उर्वरक रेकों को संयंत्रों और बंदरगाहों से गंतव्य स्थलों के लिए भेजा गया, जो लॉकडाउन के दौरान एक दिन में भेजी गई उर्वरकों की सबसे ज्यादा खेप है। एक रेक अर्थात एक पूरी ट्रेन एक बार में 3,000 मीट्रिक टन भार ले जाती है। उर्वरक संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत देश में उर्वरक संयंत्रों के संचालन की अनुमति प्रदान की है, जिससे लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित न हो सके। उर्वरक संयंत्रों, रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों पर उर्वरकों को चढ़ाने और उतारने का काम तेजी के साथ हो रहा है, इसलिए इस दौरान कोविड संक्रमण से बचने के लिए सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। श्रमिकों और कर्मचारियों को मास्क और अन्य सभी निवारक उपकरण प्रदान किए गए हैं।

सीसीएल में सादगी से मना मजदूर दिवस

रांची : कोरोना महामारी ने हमारी जीवनशैली सहित हमारे तौर तरीके भी बदल दिए है । सीसीएल ने इस परिवर्तन को स्वीकारा भी है और इसका अनुपालन भी नियमानुसार कर रहा है। कम्पनी के बदले हुए इस नए अंदाज का जीवंत उदाहरण इस वर्ष के 'अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस' के अवसर पर देखा गया जब हर वर्ष की भांति कम्पनी के कर्मियों ने अपने दिवंगत कोयला कर्मियों को श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित किये और साथ ही सीएमडी गोपाल सिंह के मार्गदर्शन में राँची शहर के विभिन्न स्थानों जैसे जगन्नाथपुर मंदिर, ओवरब्रिज, जवाहरनगर आदि पर गरीब परिवारों के बीच 300 खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किये । मई दिवस समारोह तथा खाद्य सामग्री वितरण करते समय 'सोशल डिस्टेंसिंग', मास्क सहित अन्य आवश्यक निर्देशों का पालन अनुशासन के साथ किया गया। कार्यक्रम का सफल निर्वहन महाप्रबंधक (प्रशासन) डॉ ए के सिंह, मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) संजय कुमार, राजू प्रसाद एवं अन्य द्वारा किया गया।

प्रत्येक खाद्य पैकेट में 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, 3 किलो आलू, 2 किलो प्याज़, 2 किलो दाल, 2 लिटर तेल व हल्दी आदि थे ।

Quality With
देव मेडिसिन्स
आप के प्यारे पेट्स पशुधन, जानवरों की सारी दवाईयां, वेक्सिन फूड एवं सभी एक्सेसरीज उपलब्ध
रातू रोड, नियर मेट्रो गली रांची
फोन :9334935339

गांव छोड़ब नाही आखिर कैसे संभव होगा?

झारखंड की भौगोलिक स्थिति, यहां की जलवायु कुछ ऐसी है कि यहां पहले चाय ,काजू तक की खेती होती थी, आज स्ट्राबेरी, और एलोवेरा की खेती भी कुछ किसान सफलतापूर्वक कर रहे हैं। बीएयू और हार्टिकल्चर के वैज्ञानिकों का कहना है कि झारखंड में फूलों की खेती के लिये सबसे बेहतर मौसम और जलवायु है। अगर इन सब पर ध्यान दें तो एक बड़ी आबादी पलायन नहीं करेगी और ये पर्यावरण अनुकूल रोजगार साबित होगा। अक्सर ये खबर छपती है कि गांवों में किसी ने स्ट्राबेरी की खेती कर लाखो कमाने शुरू कर दिये, एलोवेरा की खेती कर प्रचुर आमदनी प्राप्त करने लगा, तालाबों में मछली पालन कर या किसी व्यावसायिक फसल की खेती से बिना किसी की चाकरी किये कोई लाखो की आमदनी कर रहा है तो ये लगता है कि झारखंड में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ऐसी कृषि का बढावा देकर यहां से पलायन रोका जा सके।

मनोज कुमार शर्मा

झारखंड के प्रतिष्ठित लोककवि, गायक कलाकार मधु मंसुरी जी का गीत गांव छोड़ब नाही बहुत मधुर और अच्छा संदेश लिये हुये है, लेकिन ये सचमुच जमीन पर उतरता नहीं है। लाखो युवा हर साल राज्य से पलायन कर दुसरे राज्यों में जाते हैं और इनमें से ज्यादतर कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते वहां उनका शोषण होता है।

गांव छोड़ नगरों को जाकर देखना और निहारना कोई नयी सोंच नहीं है। गांव हमेंशा नगरों की भव्यता, सुख सुविधा के साधनों की उपलब्धता और प्रचुर धन की चाह में उधर देखता रहा है। भारत के बहुत सारे गांवों में तो बिजली दो दशक पहले पहुंची है ऐसे में बेहतर सुख साधनों धन वैभव की प्राप्ति के लिये शहरों की ओर पलायन होता ही है। ये लोग वहां परिश्रम करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने गांव भेजते हैं। एक नजर में ये सही भी है, पर जब हम देखते हैं कि राज्य में कुछ किसान अपनी सफल खेती से नजीर पेश कर रहे हैं और बाहर अच्छी खासी नौकरी छोड़ अपने गांव में आकर व्यावसायिक खेती कर रहे युवा लाखो कमा रहे हैं औरों को रोजगार भी दे रहे हैं तो यह उम्मीद जगती है कि कृषि के क्षेत्र में झारखंड में बहुत कुछ संभव है।

आखिर झारखंड कैसे मत्स्यपालन में आत्मनिर्भर हो गया? इस एक उपलब्धि को हम आधार माने तो राज्य फूलो की खेती में नजीर पेश कर सकता है। ग्रीनरिवोल्ट ने अक्टूबर 2019 में डॉ. के. के. झा (हेड हॉर्टीकल्चर, बीएयू, रांची)से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि झारखंड में फूलों की खेती में बहुत ज्यादा संभावनायें हैं और इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। एक बार योग गुरू बाबा रामदेव ने रांची में बताया था कि हमारी आयुर्वेद की दवाओं के लिये बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियों पेड़ पौधों की जरूरत झारखंड से पूरी होती है। यानि झारखंड में अगर इन औषधीय पौधों की खेती की जाये तो यह एक रोजगारपरक खेती होगी। राज्य में साग सब्जियों की अच्छी खेती होती है और कई क्षेत्रों में कुछ प्रयास हो भी रहे हैं, पर अभी इन क्षेत्रों में जो कुछ किया जाने की जरूरत है।

कोविड -19 ने एक मौका भी उपलब्ध कराया है कि वापस लौटे झारखंडियों को यहीं रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास हों। उत्तराखंड के गांव से वीरान भूतहा हो गये और उनके खेत व्यावसायिक खेती करने वाले बाहर के किसानों ने लीज पर लेकर व्यावसायिक खेती की और अच्छी कमाई कर रहे हैं। झारखंड में भी बाहर गया मजदूर सिर्फ धान रोपने और काटने के समय ही यहां आता है फिर कमाने के लिये महानगरों में वापस चला जाता है।

झारखंड में व्यावसायिक कृषि और बागवानी में जितनी संभावनायें है वो पर्याप्त है अगर सरकार संकल्पित होकर इन्हें विकसित करने का प्रयास करे तो एक बड़ी आबादी पलायन से बच जायेगी। क्योंकि कुछ प्रतिशत युवाओं को छोड़ दें तो अपना गांव कोई छोड़ना नहीं चाहता।

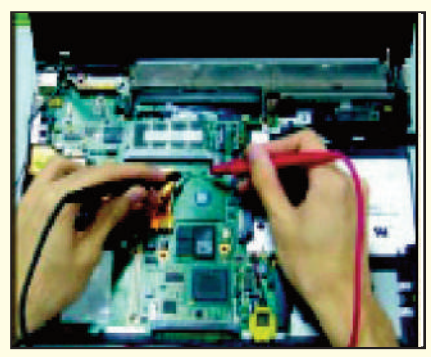

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road,
Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

शर्मनाक हरकत

लॉकडाउन के शुरूआती दौर में ज्यादा सख्ती नहीं की गयी थी। सरकार का ये मानना था कि लोग संक्रमण के भय से खुद ही सतर्क रहेंगे और लॉकडाउन का पालन करेंगे। लेकिन लोगों ने तरह तरह के बहाने बना कर बाहर निकलना और घूमना फिरना चालू रखा। इससे कोराना पर लगाम लगाने का प्रयास कमजोर होते दिखने लगा और सरकार ने पुलिस फोर्स बढा कर लाकडाउन को सख्ती से लागु करने का प्रयास किया। उसके बाद देश भर में लोगों ने जहां तहां पुलिस पर ही पथराव करने शुरू कर दिये। कुछ को अपने धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता थी इसलिये पुलिस और कानून को ठेंगा दिखाया गया , वहीं कुछ को ये लगता था कि कोरोना उन्हें छू नहीं सकता इसलिये ये बंदिश बेकार है और इसलिये वो विरोध स्वरूप पुलिस पर ही हमले करने लगे।

ये पूरा घटनाक्रम भविष्य में भी देशवासियों पर एक धब्बे के समान रहेगा। यहां ये याद रखना होगा कि ये लॉकडाउन हमारी ही जान बचाने के लिये है। और दुश्मन कोई अपराधी, आतंकी या दंगाई तत्व नहीं बल्कि एक वायरस है जो छुआछूत से फैलता है। बाहर जो पुलिस और अस्पतालों में जो डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्साकर्मी ड्यूटी पर है वो खुद इसका शिकार हो रहे है, पुलिसकर्मी जान हथेली पर लेकर ड्यूटी कर रहे हैं और अपने घर जाकर भी किसी अछूत की तरह बाहर ही भोजन कर रहे हैं,उनके बच्चे और परिवार वाले दूर से देख रहे हैं। इसके बावजूद वो संक्रमित हो रहे हैं और कई अपनी जान भी गंवा चुके हैं।लेकिन भारत की जनता

लॉकडाउन के दरम्यान भारत में जितने जानलेवा हमले डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों पर हुये हैं उतने दुनिया में कहीं और नहीं हुये होंगे। भारत के लिये ये शर्म की बात है कि विश्व के लोग ये सोंच रहे होंगे कि भारतीय आखिर अपने बचाने वालों पर ही जानलेवा हमले क्यों कर रहे हैं? पुलिस पर पथराव, मुहल्ले की पूरी आबादी का डॉक्टरों की टीम पर टूट पड़ना, पुलिसकर्मी का हाथ काट डालना, महिलाओं का भी पत्थरबाजी में शामिल होना अपने आप में एक शर्मनाक घटना है और ये सब सिर्फ इसलिये कि हम कानून को नहीं मानते? और इसमें माननीयों से लेकर वो लोग भी शामिल हैं जिन पर खुद ये सब रोकने का दारोमदार था।

इन पुलिसकर्मियों को धौंस दिखाने, इन्हें चकमा देने, इन्हें पत्थर मारने लगी रही है। डॉक्टर खुद संक्रमित होकर जान गवां कर लोगों का ईलाज कर रहे हैं और लोग मुहल्लों में उन्हें पत्थर मार रहे हैं, मकान मालिक संक्रमण के भय से उन्हें घरों से निकालने की धमकी दे रहे हैं। कोरोना संकट तो आज है कल खत्म हो ही जायेगा लेकिन एक बड़ी आबादी ने शर्मनाक कृत्य किया है। भविष्य में यही सुनाया जायेगा कि कोरोना संकट काल में जान बचाने वालों को ही एक तबका मारते पीटते रहा।

कोरोना का संदेशः चलो गांव की ओर

प्रभात झा

आजादी के बाद दशकों तक सरकारी नीतियां ऐसी रहीं कि शहर फैलता गया और गांव को निगलता गया। महानगरों के आसपास के गांव दुबकते गए, वहीं गांव में शहर घुस आया। शहर अमीर होते चले गए और गांव गरीब। शहर खाने वाला, जबकि गांव उगाने वाला बन कर रह गया।

जीवन हो, समाज हो, संस्था हो या राष्ट्र हो, इन सभी में प्रारंभ से ही उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी भी इसी तरह की एक घटना है। सुघटना हो या दुर्घटना, दोनों के ही दो पहलू देखे जा सकते हैं। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। कोरोना का नकारात्मक पक्ष यह है कि वह मानव का जीवन समाप्त कर रहा है। वहीं, उसका दूसरा पक्ष है कि कोरोना के कारण शहरों में रहने वाले परदेसी लोगों को गांव की बहुत याद आ रही है। ग्रामीण परिवेश से निकल कर भारत के भिन्न-भिन्न शहरों और बड़े-बड़े महानगरों में जीविकोपार्जन के लिए जाने वाले गांव भूल गए और आज उन्हें सबसे ज्यादा गांव की याद आ रही है।

वैश्विक महामारी कोरोना का संदेश है कि गांव और शहर के बीच में सदैव संतुलन रहना चाहिए। जैसे संतुलित आहार शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही गांव और शहर का संतुलन रहने से ही भारत की संस्कृति भी बचेगी और प्रगति भी होगी। भारत के गांव वैदिककाल से ही प्रतिभा संपन्न थे। गांव में ज्ञान था, विज्ञान था, वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, महाभारत था और रामचरितमानस भी। भारत की ग्राम्य सभ्यता और संस्कृति की विश्व में धाक थी। महात्मा गांधी ने 1909 में 'हिंद स्वराज' में भारतीय गांवों का चित्र खींचते हुए भारतीय ग्राम संस्कृति को विश्व संस्कृति बताया था। उन्होंने जोर देकर कहा था, 'अगर गांव नष्ट होता है तो भारत भी नष्ट हो जाएगा, भारत किसी मायने में भारत नहीं रहेगा।' उन्होंने 'गांव को भारत की आत्मा' कहा था। उनका मानना था कि न केवल भारत, बल्कि विश्व व्यवस्था का उज्ज्वजल भविष्य भी गांवों पर निर्भर करता है। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक सरकारी नीतियां ऐसी रहीं कि शहर फैलता गया और गांव को निगलता गया। महानगरों के आसपास के गांव दुबकते गए, वहीं गांव में शहर घुस आया। शहर अमीर होते चले गए और गांव गरीब। शहर खाने वाला, जबकि गांव उगाने वाला बन कर रह गया। शहर की स्वार्थी सभ्यता ने गांव को गुलाम बना दिया। शहरी लालच में गांव वीरान होने लगा। किसी ने सुध नहीं ली, न सरकारों ने, न व्यक्ति ने और न ही समाज ने। इन सबका दुष्परिणाम आज सामने है। 1951 में भारत की तिरासी फीसद आबादी गांवों में रहती थी, जो आज घट कर उनहत्तर फीसद रह गई है। गांव समृद्ध हो, इसकी न नीयत रही है और न नीति। 1951 में गांव का बजट का कुल बजट का 11. 4 फीसद था, 1960-61 में यह बारह फीसद, 1970-71 में साढ़े नौ फीसद, 1980-81 में 10.9 फीसद, 1990-91 में 10.8 फीसद, 2000-01 में 9.7 फीसद और 2019-20 में 9.83 फीसद रहा। वहीं 1970-71 में देश के कुल कार्यबल का चौरासी फीसद गांवों में था, जो 1980-81 में घट कर 80.8 फीसद, 1990-91 में 77. 8 फीसद, 2010-11 में 70.9 फीसद और वर्तमान में घट कर लगभग सत्तर फीसद रह गया है। देश के सत्तर फीसद कार्यबल के लिए दस फीसद से भी कम बजट। ऐसे में गांव की समृद्धि में अभिवृद्धि कैसे हो सकती है? ग्राम स्वराज्य का सपना कैसे पूरा हो सकता है? आजादी के बाद देश की बागडोर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के हाथ में आई थी। पर आजादी के बाद महात्मा गांधी के विचारों, खासकर उनके ग्राम स्वराज के विचारों की सबसे अधिक अनदेखी अगर किसी ने की तो वे जवाहरलाल नेहरू ही थे। हालांकि वे अपने भाषणों में कहा करते थे, 'सब कुछ इंतजार कर सकता है, पर कृषि नहीं'। पर उनकी करनी में कहीं पर भी कृषि को महत्त्व नहीं दिया गया। भारत गांवों का देश है, अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों ने यही बात कही है।

कौन नहीं जानता भारत गांवों में बसता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गांव की कितनी चिंता की गई? डेढ़ वर्षों के अपने अल्प कार्यकाल में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गांव और किसान की चिंता करते हुए 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया था। गांव और किसान के जीवन में आशा की नई किरण का संचार हुआ, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु ने आशा की उस किरण को भी मृत कर दिया। नतीजा यह हुआ कि गांव और शहर का संतुलन बिगड़ता गया, भ्रष्टाचार और लालच गांव की संस्कृति और संवृद्धि को निगलता गया। गांव की समृद्धि ही भारत की समृद्धि है। भारत एक वेद है। हजारों गांव इस वेद की ऋचाएं हैं। वेद में प्रत्येक ऋचा का अलग भाव और व्यक्तित्व है। भारत के प्रत्येक गांव का भी अलग भाव और व्यक्तित्व है। लेकिन आज का सच क्या है? गांव शहर का उपनिवेश बनता जा रहा। शहर अमीर है, गांव गरीब है। गांवों में अस्पताल नहीं हैं। अगर हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी नहीं हैं। स्कूलों की भी हालत अच्छी नहीं है। आज चूल्हे से मुक्ति जरूरी है, वन की रक्षा हुई है।

स्किल इंडिया जरूरी है, लेकिन इसकी सफलता गांव में लघु-कुटीर उद्योग के रूप में है। प्रकृति और संस्कृति के सौंदर्य की रक्षा करते हुए गांव की रक्षा होनी चाहिए। गांव में संवृद्धि आए, लेकिन बिना किसी विकृति के। विकास की नीतियां ऐसी हों, जिसमें गांव-शहर का संतुलित विकास हो। शहर बाजार है, तो गांव संस्कृति और विचार। संवृद्धि का आधार सांस्कृतिक हो, प्राकृतिक हो, संस्कृतिविहीन और प्रलयकारी नहीं।

वैश्विक महामारी कोरोना से आज विश्व का हर राष्ट्र हिल गया है। उसके इलाज के लिए टीके या दवा की खोज में पूरी दुनिया लगी है। अनेक संस्थाएं, जो गांव आधारित सर्वे और विश्लेषण करती हैं, उनका मानना है कि कोरोना से भारत अब भी इसलिए बचा है क्योंकि अधिकांश आबादी गांवों में बसती है। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी यही कहना है। गांवों में शुद्ध जल है, शुद्ध हवा है, पेड़-पौधे हैं, नदी है, सरोवर हैं, पर्वत हैं, खेत हैं, खलिहान हैं। लेकिन शहरों-महानगरों ने प्रकृति के पंच महाभूतों- क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर पर धावा बोल कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया है। गांव, खेत-खलिहान, वन-उपवन की छाती चीरते शहर सीमेंट कंक्रीट की बेतरतीब इमारतें लेकर फैलते जा रहे हैं। गंदे नाले, खराब जल, प्रदूषित हवा के कारण शहर-महानगर महामारी के शिकार हो रहे हैं। कारण है, गांवों से शहरों में अनियोजित पलायन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45.36 करोड़ अंतरराज्यीय प्रवासी हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का सैंतीस फीसद है। वहीं हाल के आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि शहरों में प्रवासी कार्यबल की आबादी दस करोड़ (बीस फीसद) से अधिक है। केवल दिल्ली और मुंबई में यह आबादी लगभग तीन करोड़ है।

2019 में किए गए एक अध्ययन की मानें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता महानगर और हैदराबाद, बंगलुरु जैसे देश के बड़े शहरों की उनतीस फीसद आबादी दैनिक मजदूरों की है।आज कोरोना महामारी से शहरों-महानगरों में उत्पन्न कंपन और डर ने रेलवे की पटरियों पर झुग्गी बस्तियों, रेलवे पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे बने अस्थायी बस्तियों में रहने वाले, मुंबई की धारावी जैसी झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के मन में अब आने लगा है कि गांव का फूस और खपरैल का घर इन नारकीय बस्तियों से बेहतर है। कोरोना माहामारी के इस काल में लोगों में आतुरता बढ़ी है और सहज कहने लगे हैं -'चलो गांव की ओर' पूरे देश को खिलाने की ताकत गांवों में है। इसी ताकत के कारण कोरोना महामारी में भारत आज बचा है। इसी ताकत के कारण भारत आज बचा है।

वायरस के डर से लोग जानवरों को छोड़ रहे हैं

एजेंसियां:कोरोना वायरस के कारण आवारा जानवरों के सामने भी खाने का संकट है। आवारा कुत्ते, गाय को पहले जहां खाना मिल जाया करता था वही अब भूखे रहने को मजबूर हैं। कुछ एनजीओ और लोग अब ऐसे जानवरों की मदद को आगे आए हैं।कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट शेयर की जा रही हैं। कुछ पोस्ट जानवरों से भी जुड़ी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पालतू जानवरों से भी कोरोना वायरस फैलता है, हालांकि यह अब तक साबित नहीं हुआ है कि जानवरों के कारण कोरोना वायरस फैलता है। भारत में भी कई लोग अपने पालतू जानवरों को सड़क पर छोड़ दे रहे हैं। आवारा पशुओं और कुत्तों के लिए काम करने वाले समूह और कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोविड-19 के कारण जानवरों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है।

जानवरों के लिए काम करने वाले एनजीओ और कार्यकर्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जानवरों को छोड़ देने की घटनाएं बढ़ी हैं। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्तों और बिल्लियों के लिए शेल्टर होम लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए हैं। यही नहीं आवारा जानवरों के साथ इस दौरान क्रूरता के मामले भी बढ़े हैं। कई बार तेज रफ्तार गाड़ियां भी उन्हें टक्कर मार दे रही है। पीपल फॉर एनिमल (पीएफए) ट्रस्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु कल्याण संगठन है, वह हर रोज ऐसे आवारा जानवरों के लिए कैंप लगाता है जो जख्मी हो गए या फिर उन्हें मेडिकल मदद की जरूरत है। इस संगठन के 36 अस्पताल हैं और ढाई लाख के करीब सदस्य हैं। संगठन के सदस्य कोविड-19 के खतरे के बावजूद घरों से बाहर निकल आवारा कुत्तों को भोजन दे रहे हैं।

क्यों पस्त हो गया अमेरिका कोरोना वायरस से?

रमेश शर्मा

ओबामा ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ट्रंप के साथ मिलकर एक काल्पनिक महामारी के खिलाफ अभ्यास किया था और पूरी रणनीति उनके सुपुर्द की थी। लेकिन ट्रंप ने सत्ता संभालते ही उसे दरकिनार कर दिया और उस विभाग को ही खत्म कर दिया।

कोरोना वायरस के सामने दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे धनी देश अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं में वहां तीसरी दुनिया कहे जाने वाले देशों जैसी लाचारी दिख रही है। दशकों से महामारियों और अन्य विपदाओं के खिलाफ दुनिया का हाथ थामने वाला अमेरिका खुद बैसाखियां ढूंढ रहा है।अपने-अपने घरों में बंद अमेरिकी जनता हर सुबह इस उम्मीद के साथ जगती है कि महामारियों पर बनी हॉलीवुड की डरावनी फिल्मों की तरह शायद इस वायरस का भी अंत निकट हो। लेकिन हर सुबह और ज्यादा मौतों की खबर ला रही है। दुनिया की वित्तीय राजधानी कहलाने वाले न्यूयॉर्क में लाशों को सामूहिक रूप से दफनाया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया राष्ट्रपति ट्रंप पर उंगली उठा रहा है, ट्रंप मीडिया और चीन दोनों को कोस रहे हैं। जानकारों की मानें तो स्थिति को बिगड़ने देने में ट्रंप और उनके प्रशासन की गलती तो है ही, पिछले दो दशकों से चली आ रही अमेरिकी नीतियां भी इसकी जिम्मेदार हैं। पिछले बीस सालों में हर प्रशासन के सामने विशेषज्ञों, सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्टों और खुफिया अधिकारियों ने कोरोना वायरस जैसी महामारी की तस्वीर पेश की है, उसके खिलाफ तैयार रहने की सलाह दी है। लेकिन हर नए राष्ट्रपति ने पुराने राष्ट्रपति की सलाहों को नजरअंदाज किया है और फिर जब विपदा आई है तब जाकर तैयारियां शुरू हुई हैं, टास्कफोर्स बने हैं। विपदा के काबू में आने के बाद सब कुछ फिर जस का तस। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में जैविक हथियारों से हमलों और इस तरह की महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए स्वास्थ्य उपकरणों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षित कपड़ों और मास्क का आपातकालीन भंडार तैयार करने के लिए एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति की थी। अमेरिका में कोरोना विस्फोट की कई वजहें हैं, हालांकि कई जानकार आशंका जता रहे हैं कि सबसे बदतर स्थिति अभी आनी बाकी है। इस वक्त अमेरिका में इस वायरस के सबसे ज्यादा मामले हैं। राष्ट्रपति बुश ने 2001 में सत्ता संभालते ही उस पद को खत्म कर दिया लेकिन ग्यारह सितंबर के हमले के बाद उनकी नीति भी बदली। अमेरिका जैविक और रासायनिक हथियारों के खतरे के प्रति सचेत हुआ। कुछ ही दिनों में बुश प्रशासन ने सार्स बीमारी का सामना किया और अपने अनुभवों को अगले राष्ट्रपति ओबामा के साथ साझा किया। लेकिन ओबामा ने भी पहले उसे नजरअंदाज ही किया। ये वही ओबामा थे जिन्होंने छह साल पहले एक सेनेटर के रूप में न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख लिखकर इस तरह की महामारी के खिलाफ अमेरिका और दुनिया को तैयार रहने की नसीहत दी थी।

राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी आंखें खोलीं एच1एन1स्वाइन फ्लू और फिर इबोला के संकट ने। और उन्होंने इस तरह की महामारियों से जूझने के लिए एक पूरी नीति तैयार की जिसके तहत एक अलग विभाग का भी गठन हुआ। उनके अनुभवों ने एक कारगर नीति की बुनियाद रखी जिसका मकसद न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को ऐसी विपदा के खिलाफ तैयार रखना था। ओबामा की टीम ने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ मिलकर एक काल्पनिक महामारी के खिलाफ अभ्यास भी किया और एक पूरी रणनीति उनके सुपुर्द की। ट्रंप की टीम ने सत्ता संभालते ही उसे दरकिनार कर दिया और पिछले साल ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बॉल्टन ने ओबामा के बनाए ग्लोबल हेल्थ सेक्योरिटी ऐंड बायोडिफेंस विभाग को ही खत्म कर दिया।

अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महामारियों और बीमारियों को रोकने के लिए 1946 में बनी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) का बजट (मुद्रास्फीती को ध्यान में रखते हुए) घटता ही चला गया है। ट्रंप प्रशासन के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीडीसी के लिए डेढ़ अरब डॉलर की मांग की थी, उन्हें उसका आधा बजट दिया गया। अफरातफरी के माहौल में कोरोना वायरस की बड़े स्तर पर टेस्टिंग के लिए सीडीसी ने जो किट बनाया वह पूरी तरह से विफल रहा और उसके बाद जाकर निजी क्षेत्र की कंपनियों के बनाए किटों के इस्तेमाल पर पाबंदियां हटाई गईं। लेकिन इन सबके बीच कीमती समय बर्बाद हो चुका था और वायरस अमेरिका को अपनी चपेट में ले चुका था। ग्यारह सितंबर के हमलों के बाद जो आकलन हुए थे उनसे स्पष्ट था कि अमेरिकी खुफिया और तमाम एजेंसियों के बीच तालमेल की न सिर्फ कमी थी बल्कि सभी अपने-अपने बंद दरवाजों के बीच काम कर रहे थे। नौकरशाही की परतों के बीच, वे अहम जानकारियां जिनसे उन हमलों को रोका जा सकता था गुम हो गईं। कोरोना वायरस के खिलाफ भी काफी हद तक वही स्थिति नजर आई है। अमेरिकी मीडिया में हर दिन खबरें आ रही हैं कि फलाना वैज्ञानिक ने प्रशासन को आगाह किया था, कि खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्टें पेश की थीं लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। ट्रंप की कड़ी आलोचना हो रही है कि वे इस खतरे की गंभीरता को नकारते रहे, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की राय सुनने की बजाय अनुभवहीन सलाहकारों की सुनते रहे और अपने राजनीतिक समीकरणों को तोलते रहे। महामारियों के जो जानकार थे या फिर जिन्हें पहले की महामारियों का अनुभव था, वे तस्वीर में कहीं थे ही नहीं। उप-राष्ट्रपति माइक पेंस के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बना वह अफरातफरी में ही बना और उन्हें भी ट्रंप को खुश रखने और सही नीतियां लागू करने के बीच संतुलन बनाते हुए काम करना पड़ रहा है। वेंटीलेटर्स और आधुनिक उपकरणों की भारी कमी नजर आई है। दुनिया की मदद करने की बजाए अमेरिका कभी दबंगपने से तो कभी दोस्ती से अन्य देशों से मदद मांगता नजर आया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति ने अमेरिका के मित्र देशों और दुनिया को पहले से ही आहत कर रखा था, एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में उसकी भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। अब चीन से टकराव और अनाप शनाप बयानबाजी से लगता है कि दुनिया का नेतृत्व करने की उसकी क्षमता पर भी सवाल उठेंगे।

बांग्लादेश की नदियों में खतरनाक एंटिबायोटिक्स

बांग्लादेश में पानी के स्रोतों जैसे तालाब, नहरों, झीलों, नदियों में एंटीबायोटिक्स दवाओं और केमिकल्स के भारी मात्रा में अंश मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सतह की जल सम्पदा में मौजूद यह एंटीबायोटिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। जिससे देश में एंटीबायोटिक रेसिस्टेन्स का खतरा बढ़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एंटीबायोटिक रेसिस्टेन्स से तात्पर्य है कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरसों और परजीवियों पर एंटीबायोटिक दवाओं का बेअसर होना। ऐसा तब होता है जब गैर जरुरी होने पर भी ज्यादा मात्रा में इन एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसके चलते धीरे धीरे यह सभी बीमारी फ़ैलाने वाले घटक इन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हो जाते हैं और उनपर इन दवाओं का असर नहीं होता है। जिसके कारण संक्रामक रोगों की रोकथाम, उपचार और प्रसार को रोकना मुश्किल हो जाता है।

शोध के अनुसार जिस तरह से एंटीबायोटिक्स का उपयोग बढ़ रहा है, उसने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। इन देशों में आज भी इन दवाओं को लेकर कोई तय मानक और नियम नहीं हैं। यहां आज भी बिना किसी रोकटोक के स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में धड़ल्ले से इन रोगाणुरोधी दवाओं का उपयोग हो रहा है। वहीं दूसरी ओर उचित प्रबंधन के आभाव में इन दवाओं के अपशिष्ट तेजी से भूमि और साफ़ जल स्रोतों को भी दूषित करते जा रहे हैं और बांग्लादेश और भारत जैसे देशों में एंटीबायोटिक रेसिस्टेन्स का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है।

लुप्त हो जायेंगी कोर रीफ्स

अनुमान है कि सदी के अंत तक प्रवाल भित्तियां (कोरल रीफ्स) दुनिया से पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी। जबकि अगले 20 वर्षों में ही इसकी 70 से 90 फीसदी आबादी के खत्म हो जाने का अनुमान है। वैज्ञानिकों इसके लिए दिन प्रतिदिन जलवायु में आ रहे बदलाव, प्रदूषण और समुद्रों में बढ़ रहे अम्लीकरण को बड़ी वजह मान रहे हैं। यह हैरान कर देने वाली जानकारी सैन डिएगो में चल रही ओसियन साइंस मीटिंग 2020 में प्रस्तुत किये नए शोध से पता चली है। साथ ही, शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि इन क्षेत्रों की बहाली के लिए चलायी जा रही परियोजनाएं गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं हालांकि कुछ वैज्ञानिक समूह कृत्रिम रूप से उगाई गयी प्रवाल भित्तियों को को मृत भित्तियों में प्रत्यारोपित करके इस गिरावट को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि इन युवा कोरल रीफ की मदद से प्रवाल भित्तियों को बचाया जा सके। इसके बावजूद दुनिया में कई जगह पर प्रवाल भित्तियां पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी

क्या सिगरेट बचा सकता है कोरोना वायरस से?

मुरलीधर

फ्रांस में हुए एक हालिया शोध के अनुसार निकोटीन कोरोना वायरस को शरीर में जाने से रोकती है। तो क्या कोरोना से बचने के लिए सिगरेट पीने लगें ?अब तक यही माना जाता रहा है कि सिगरेट पीने वालों को कोविड-19 का खतरा ज्यादा होता है। चीन में हुए एक शोध के अनुसार इन लोगों को सिगरेट ना पीने वालों की तुलना में भीषण संक्रमण होता है और इनकी जान जाने की संभावना भी अधिक होती है। लेकिन अब फ्रांस में हुआ एक शोध कुछ और ही कह रहा है। फ्रांस के इंस्टीट्यूट पैस्टर के न्यूरोबायलॉजिस्ट यौं पिएर शॉज के अनुसार निकोटीन वायरस के संक्रमण को रोकने में मददगार होता है। इनके अनुसार कोविड-19 के मरीजों में सिगरेट पीने वालों की तादाद काफी कम है।

फ्रांस में हुए इस शोध में कोरोना संक्रमित 500 मरीजों का डाटा जमा किया गया। इनमें से 350 का इलाज अस्पतालों में हुआ था और 150 को हल्के लक्षण ही थे। शोध से जुड़े प्रोफेसर जाहिर अमोरा ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि इनमें से केवल पांच फीसदी लोग ही सिगरेट पीते थे। उनका कहना है, "इसका मतलब हुआ कि आम जनता के मुकाबले यहां 80 फीसदी कम स्मोकर हैं।"

यह इस तरह का पहला शोध नहीं है। इससे पहले इटली में जिसेप लिपी की टीम भी इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंची थी। उस शोध को यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित किया गया था। उस शोध में सिगरेट के फायदे की तो कोई बात नहीं की गई थी पर यह जरूर कहा गया था कि सिगरेट पीने वालों को बाकियों की तुलना में ज्यादा खतरा नहीं होता।

साइनस में रुकावट

एक सिगरेट पीने के फौरन बाद नाक, आंख और माथे में मौजूद खोखले साइनस में बाधा आने लगती है। नाक हल्की बंद सी हो जाती है लेकिन शोध इस ओर इशारा करता है कि

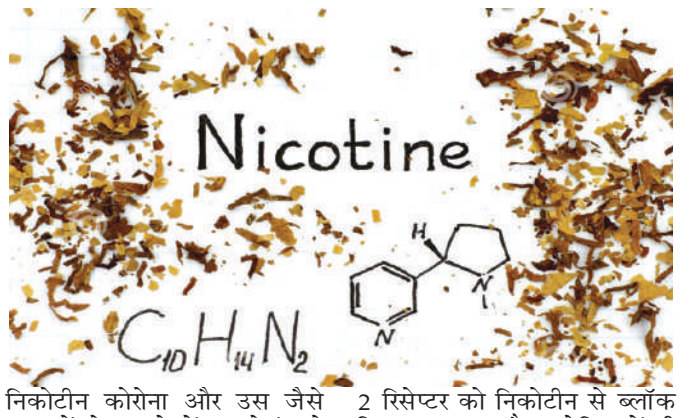

निकोटीन कोरोना और उस जैसे वायरसों से बचाने में फायदेमंद हो सकती है। शोधकर्ता शॉज बताते हैं, "निकोटीन खुद को सेल रिसेप्टर एसीई-2 से जोड़ लेती है। इसी का इस्तेमाल कोरोना वायरस भी करता है। लेकिन निकोटीन के जुड़े होने से वायरस ऐसा नहीं कर पाता है।" इस दावे की अब फ्रांस के अस्पताल में जांच होनी है।

वैज्ञानिकों के बीच फिलहाल इस पर कोई सहमति नहीं है कि एसीई-2 रिसेप्टर को निकोटीन से ब्लॉक किया जा सकता है। अमेरिका में भी इस पर शोध किया गया और वहीं नतीजे बिलकुल ही विपरीत दिखे। 18 मार्च को एफईबीएस जर्नल में छपी इस रिसर्च के अनुसार निकोटीन सेल रिसेप्टर को और सक्रीय कर देता है जिससे वायरस के लिए कोशिका में प्रवेश करना और भी आसान हो जाता है। शोध के अनुसार, "इससे समझा जा सकता है कि सिगरेट पीने वालों में लक्षण इतने भीषण क्यों होते हैं।तो फिर सही कौन है? फ्रांस के रिसर्चर या अमेरिका के? इसका जवाब सिर्फ तब ही मिल सकता है जब इस दिशा में और ज्यादा शोध हो। लेकिन फिलहाल दुनिया के अधिकतर डॉक्टर मानते हैं कि सिगरेट पीना कोरोना से बचने के लिए अच्छा नहीं हो सकता। वे तो लोगों को जल्द से जल्द सिग्रेट छोड़ने की हिदायत भी दे रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कोरोना वायरस फेफड़ों पर वार करता है और सिगरेट पीने वालों के फेफड़े पहले ही कमजोर होते हैं। हालांकि निकोटीन पैच का असर अलग होता है।

फेफड़ों के साथ क्या करता है कोरोना?

सिगरेट की लत छोड़ने की कोशिश करने वालों के शरीर पर कई बार निकोटीन का पैच लगाया जाता है। इससे शरीर को बिना सिगरेट के ही निकोटीन मिल जाती है जिसकी शरीर को तलब होती है। इसके विपरीत सिगरेट पीने के दौरान कागज जलता है, धुआं निकलता है और कैंसर पैदा करने वाले कई तत्व निकलते हैं। एक सिगरेट में 12 मिलीग्राम निकोटीन होती है लेकिन शरीर एक से तीन मिलीग्राम ही सोखता है। तो अगर फ्रांस वाला शोध सही साबित होता है तो निकोटीन का पैच लगा कर लोगों को कोरोना संक्रमण से रोका जा सकेगा। यहां तक कि जो लोग कोविड-19 के मरीजों से संपर्क में आए हों, उन्हें भी बचाया जा सकेगा।

इससे पहले भी विज्ञान जगत में निकोटीन पर शोध होते रहे हैं। अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों के इलाज में इसके असर को समझने की दिशा में काफी रिसर्च हुई है। डिमेंशिया जैसी भूलने की बीमारी में निकोटीन काफी फायदेमंद साबित हुई है। लेकिन कोरोना के मामले में अभी निकोटीन को लाभकारी मान लेना जल्दबाजी होगी। इस वायरस के बारे में अभी तक बहुत कम जानकारी है। ऐसे में इससे बचने के लिए सिगरेट पीना अच्छा विचार तो नहीं लगता।

भारतीय रेल की सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं 17 मई तक रद्द

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के प्रयासों को जारी रखते हुए रेलवे मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया गया है की भारतीय रेलवे की सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं 17मई तक रद्द रहेंगी। सभी लम्बी दूरी वाली मेल / एक्सप्रेस तथा इंटरसिटी ट्रेने (प्रीमियम ट्रेने भी) एवं सभी पैसेंजर ट्रेने पहले दिनांक 03मई तक रद्द थीं अब यह सभी ट्रेनें 17/05/2020 तक रद्द रहेंगी। इसी के अंतर्गत रांची रेल मंडल से चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं अब दिनांक 17/05/2020 तक रद्द रहेंगीं सभी टिकट बुकिंग काउंटर, वळर (अनारक्षित टिकट प्रणाली) एवं ढफ्र (पैसेंजर आरक्षण प्रणाली) अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिनांक 1 मई 2020 के गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य सरकार की ओर से अनुरोध करने पर ही विभिन्न राज्यों तथा जगहों पर फंसे हुए मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक,छात्र तथा अन्य व्यक्तियों को अपने गंतव्य स्थान पर जाने हेतु विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु माल गाड़ियों एवं पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन पूर्ववत चालू रहेगा

25 करोड मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य

रांची :ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रारंभ की जा रही तीन योजनाओं के माध्यम से 25 करोड मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है, इससे करीब 20 हजार करोड़ रुपये लाखों श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होगा। यह संकट का समय है। ईमानदारी व तत्परता से काम करें ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। झारखण्ड आज कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। यह बड़ी चुनौती है। हमें सीमित संसाधनों के बल पर स्वास्थ्य सुविधा, प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना है। झारखण्ड का रोजगार खेतों से जुड़ा है। संक्रमण के दौर में उद्योग बंद हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी व बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न न हो इस निमित्त कार्य योजना तैयार कर ली गई है। शुरू की गई योजनाएं निर्णायक भूमिका निभाने वाली होंगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही।

राज्य को जो चाहिए उसे धरातल पर उतारा जा रहा है: मिथलेश ठाकुर

रांची: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की झारखण्ड की धरती को जो चाहिए उसे धरातल पर उतारा जा रहा है। योजनाओं से कृषि की उत्पादकता क्षमता में वृद्धि होगी। खेल विकास योजना से राज्य की प्रतिभाओं को निखारने में सहायक होगा। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधा लगाने की योजना है, इस कार्य से किसानों को लाभ तो होगा साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो सकेगा। इन योजनाओं के माध्यम से पलायन का कलंक भी सरकार धो सकेगी।

झारखंड के मजदूरों किसानों को दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा : मुख्यमंत्री

- मजदूरों और किसानों को उनके गांव पंचायत में रोजगार उपलब्ध कराएंगे
- रोजगार सृजन के सिलसिले में अपने आंतरिक संसाधनों का कर रहे हैं आकलन
- रोजगार सृजन से जुड़े सभी संसाधनों को कड़ी के रूप में जोड़ा जाएगा

संवाददाता

रांची : झारखंड के मजदूरों- किसानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़े ' मजदूरों का पलायन रुके इस दिशा में सरकार ने पहल शुरू कर दी है ' कोरोना संकट को लेकर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को अपने ही गांव और पंचायत में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें कहीं हैं।

रोजगार सृजन के लिए कड़ियों को जोड़ने का सिलसिला शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन की दिशा में सरकार ने पहल शुरू कर दी है ' इस सिलसिले में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित किए जाने वाले 3 योजनाओं का शुभारंभ हो चुका है ' और आने वाले दिनों में इसका दायरा तेजी से बढ़ेगा ' इस सिलसिले में रोजगार के क्षेत्र में वैल्यू एडिशन का आकलन सरकार कर रही है और उसी के हिसाब से रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे '

आंतरिक संसाधनों का हो रहा है आकलन

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों की संख्या में मजदूर वापस आ रहे हैं ' ऐसे में उनको

रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है , लेकिन इस चुनौती को हम एक अवसर के रूप में ले रहे हैं ' हमने इस दिशा में अपने आंतरिक संसाधनों का आकलन करना शुरू कर दिया है ' इसी कड़ी में आज इस संस्थान की गतिविधियों और कार्यों का जायजा लिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है , बस उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है ' हमें उम्मीद है कि सरकार इस कार्य में पूरी तरह सफल साबित होगी और ना सिर्फ यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि दूसरे राज्यों से भी काम करने के लिए यहां मजदूर आएंगे।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक रॉल और गोंद संस्थान का भ्रमण किया और संस्थान द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान गतिविधियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संस्थान के पूरे परिसर का भ्रमण किया और किए जाने वाले कार्यों और अनुसंधान की जानकारी ली' संस्थान के निदेशक डॉ केके शर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि वन के साथ साथ इसे कृषि से जोड़ा जाए तो लोगों को अपने ही गांव और पंचायत में बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकेगा ' इससे ना सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा ' निदेशक ने मुख्यमंत्री से कहा कि लाख की खेती को बिरसा हरित ग्राम योजना से जोड़ने से काफी फायदा मिलेगा मुख्यमंत्री ने संस्थान परिसर में मौजूद म्यूजियम , प्रयोगशाला, लाख कीट फील्ड जीन बैंक ,उत्पादन इकाई, फार्मिंग परिसर और प्रसंस्करण इकाई का भ्रमण किया। इस मौके पर विधायक राजेश कच्छप, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, संस्थान के निदेशक डॉ के के शर्मा , सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक राजीव लोचन बख्शी, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे ।'

वीर शहीद पोटो हो योजना से खेल का विकास

रांची : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सरकार ने पंचायत स्तर पर खेल का मैदान निर्माण करने की योजना शुरू की है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के माध्यम से जहां एक ओर सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के कार्य करेगी, वहीं खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी दिया जाएगा। खिलाड़ियों को खेल के रास्ते देश व राज्य के विकास से जोड़ना है। राज्य के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों के बल पर देश और दुनिया में राज्य का मान बढ़ाया है। यहां के खिलाड़ी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से भी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। बस उसे निखारने की आवश्यकता है। इस योजना का नाम वीर शहीद पोटो हो करने का उद्देश्य वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ी को वीर शहीद की वीरता से अवगत भी कराना है। वीर शहीद पोटो हो ने सिंहभूम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। 1 जनवरी 1838 को सेरेंगसिया घाटी में वीर शहीद पोटो हो शहीद हो गए थे। इसलिए खूंटपानी में हर वर्ष पहली जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सीएमपीडीआई ने खाद्य एवं अन्य सामग्रियों का वितरण किया

संवाददातारांची : सीएमपीडीआई मुख्यालय की सीएसआर टीम द्वारा पिठोरिया थाना के अंतर्गत दहुटोला एवं राहा ग्राम में समाज के जरूरतमंद लोगों के बीच अनाज व अन्य सामग्री के पैकेट्स वितरित किए गए। सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक (एचआरडी)-सह- नोडल अधिकारी श्री आलोक कुमार ने स्थानीय प्रशासन व आचार्य निखिलेश चैरिटेबल संस्था का सहयोग लेकर कुल 800 जरूरतमंद ग्रामवासियों के बीच खाद्य सामग्री व अन्य सामग्री के पैकेट्स वितरित किया। इस पैकेट्स में 2 किलो चावल, आधा किलो दाल, हल्दी पावडर, मिक्स मसाला पावडर, 200 मि0ली0 तेल, नमक का पैकेट, 1 नहाने का साबुन, 1-1 किलो आलू एवं प्याज रखा गया था।

वर्तमान समय में लागू लॉकडाउन को देखते हुए सीएमपीडीआई द्वारा की गयी इस मदद के लिए, ग्रामवासियों ने कम्पनी को धन्यवाद ज्ञापन किया। इसके अलावा सीएमपीडीआई द्वारा पूर्व में भी कोविड-19 की रोकथाम एवं इससे बचाव हेतु 850 लीटर सैनिटाइजर एवं 4000 फेस मास्क का वितरण भी कम्पनी के निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत वितरित किया गया।

बेमौसमी बारिश से कमजोर हुआ गेहूं का दाना

राजन कुमार

इस साल जहां रबी की फसल के अच्छे होने की खबरें हैं वहीं देश में कई जगहों पर गेहूं की फसल खराब होने गेहूं की भी खबर है। दरअसल जनवरी से मार्च के दौरान बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि ने गेहूं के दाने की गुणवत्ता को खराब कर दिया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर ज्यादा देखने को मिला वहां थ्रेसर से निकालने के बाद गेहूं का दाना कमजोर था और प्रति बीघा करीब आधा गेहूं ही निकल पाया, जबकि लागत हर साल की तरह ही होती है। गेहूं की क्वालिटी सही नहीं होने के कारण व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 200 रुपये कम का भाव लगा रहा है। जबकि बरेली जिले के किसान तेजपाल ने पांच बीघे में गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन कटी-कटाई फसल खेत में ही रह गई। गेहूं का दाना कमजोर और काला है, इसलिए तेजपाल इस बात से चिंतित है कि फसल का खरीदार मिलेगा या नहीं।

ऐसे हालात केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार समेत उन राज्यों के किसानों की भी है, जहां पिछले महीनों के दौरान बारिश और ओलावृष्टि हुई। इसका असर अब देखने को मिल रहा है। यह स्थिति तब देखने को मिल रही है, जबकि किसानों को अधिक खाद व रसायन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। बावजूद इसके, फसल का उत्पादन कम हुआ। इस बात का पता चलने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तो राज्य का उत्पादन लक्ष्य ही कम कर दिया है। केंद्र को भेजी अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि प्रदेश में फरवरी व मार्च

80 के दशक में भी एक बार लगातार दो सप्ताह तक बेमौसमी बारिश होने से बिहार के किसानों की फसल खलिहान में रखे रखे ही खराब हो गयी थी। किसान तब प्लास्टिक वगैरह से गेहूं की कटी फसल को ढक तोप रहे थे, ताकि मौसम साफ हो तो थ्रेसर का उपयोग करें। लेकिन गेहूं की बालियां पानी में भीग कर खलिहान में ही अंकुरित होने लगी थी और उस साल फसल बर्बाद हो गयी थी। इस बार भी बेमौसमी बारिश ने गेहूं को कई जगहों पर बहुत नुकसान पहुंचाया है

में असामायिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से रबी की फसलों, विशेष कर दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार ने गेहूं में लगभग 2.5 प्रतिशत और दलहन व तिलहनी फसलों में 10 से 12 प्रतिशत के नुकसान का अनुमान जताया है।

दरअसल, इस बार दिसंबर से मार्च के दौरान लगातार खराब मौसम ने गेहूं की उत्पादकता पर जबरदस्त असर डाला ईसीलिए सरकारों को भी उत्पादन के बढ़े आंकड़ों को दुरुस्त करने को मजबूर होना पड़ा। मौसम विभाग (आईएमडी) के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में बारिश ने एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ा। दिसंबर में भी सर्वाधिक आठ दिन शीत लहर और बारिश ने रौद्र रूप दिखाया। आंकड़ों के मुताबिक भारत में जनवरी माह में सामान्य से 63 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। मध्य भारत इसमें सबसे आगे रहा यहां 84 फीसदी अधिक बारिश हुई। उत्तर पश्चिम भारत में 70 और पूर्वी-पूर्वोत्तर भारत में यह प्रतिशत 51 रहा। इतना ही नहीं, 1 से 19 मार्च के दौरान देश भर में सामान्य से 77 फीसदी अधिक बारिश हुई। देश के लगभग 381 जिलों (57 फीसदी) में सामान्य से 60 फीसदी बारिश हुई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा के प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉ जेपी डबास कहते हैं कि बारिश आधारित इलाकों में तो रबी की फसल को इसका फायदा हुआ लेकिन पश्चिम यूपी या आसपास के इलाकों में इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। लगातार बारिश से न तो खाद का अपेक्षित गुण लग पाया और न ही कीटनाशक का। नतीजतन ऐसे इलाकों में गेहूं की फसल कमजोर हुई। जिन इलाकों में तेज हवाएं चलीं और ओलावृष्टि हुई उसका भी नुकसान फसल और किसान दोनों को हुआ।

खराब मौसम की वजह से गेहूं की नर्सरी में प्रस्फुटन नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप गेहूं की बाली कमजोर हुई और उसका उत्पादन पर जबरदस्त असर पड़ा है। उनका मानना है कि 40 से 45 कुंतल प्रति हेक्टेयर निकलने वाला गेहूं इस बार 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर निकल रहा है। इसलिए आंकड़ों को एकत्र कर सरकार से गेहूं किसानों को अलग से प्रति कुंतल के हिसाब से आर्थिक मदद की मांग की जाएगी। इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के अध्यक्ष एवं गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के पूर्व डीन एन. रघुराम कहते हैं कि यदि पिछले साल की तरह इस साल भी फसल बोआई का क्षेत्रफल समान है और खाद व उर्वरकों का इस्तेमाल भी उतना ही किया गया है, बावजूद इसके उत्पादन कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि बेमौसमी बारिश या अचानक तेज गर्मी ने फसल की ग्रोथ पर बुरा असर डाला है।

भारत में उपजने वाले गेहूं की पौष्टिकता पहले से ही विश्व के अन्य गेहूं उत्पादक देशों से कम है ऐसे में बेमौसम बारिश की मार ने गेहूं की फसल को और नुकसान पहुंचाया है।

सीसीएल ने खरीदा 3 वेंटिलेटर अतिरिक्त 4 का कार्यादेश जारी

रांची संवाददाता : झारखंड में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, कोल इंडिया की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने सात अतिरिक्त वेंटिलेटर खरीदने का आदेश दिया जारी किया था इसमें तीन (3) आईसीयू और चार (4) पोर्टेबल वेंटीलेटर है। इसमें से कम्पनी को 3 आईसीयू वेंटीलेटर प्राप्त हो चुके है और 4 पोर्टेबल वेंटीलेटर की डिलीवरी भी जल्द हो जाएगी पोर्टेबल वेंटीलेटर का इस्तेमाल एम्बुलेंस व अस्पताल दोनों में किया जा सकता है वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल उन गंभीर कोविड-19 रोगियों की जान बचाने के लिए किया जाता है जिन्हे सांस लेने में परेशानी होती हैं सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल गांधीनगर स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है । वर्तमान में दस (10) कोविड -19 रोगियों जिनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है का इलाज गांधीनगर अस्पताल में चल रहा है। सीएमएस गांधीनगर डॉ मंजू मिश्रा तथा उनकी टीम पूरी तन्मयता के साथ प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन मरीजों का इलाज कर रहे हैं।

सीसीएल ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य को सुरक्षित रखने के लिए लगभग 3100 पीपीई की खरीदी की गयी है। सीसीएल ने समाज के जरूरतमंदो सहित अपने हितधारकों के बीच अब तक लगभग 1,32,245 मास्क वितरित किये हैं । सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी), गोपाल सिंह के मार्गदर्शन में, मेडिकल टीम कोविड -19 के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व संकट को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इससे पहले, उन्होंने "कोरोना योद्धाओं", "फ्रंटलाइन वर्कर्स" और अन्य हितधारकों के प्रति गहन आभार व्यक्त किया, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रभावित रोगियों के जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया की सीसीएल रांची सहित 8 जिलों में स्थित अपने कमांड क्षेत्रों में हर संभव प्रकार से आमजन तक सहायता पहुंचा रहा है और महामारी के समाप्ति तक यह प्रयास जारी रहेंगें

सीएमएस, सीसीएल अस्पताल डॉ सीपी धाम ने कहा कि शेष वेंटिलेटर की आपूर्ति जल्द ही गांधीनगर अस्पताल में हो जाएगी और आवश्यकतानुसार इसका इस्तेमाल कोविड -19 रोगियों को उनकी स्थितियों के आधार पर किया जाएगा । उन्होंने आगे कहा कि गंभीर मामलों में, वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शरीर के ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है इसे कम करने के लिए, वेंटिलेटर का उपयोग ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने के लिए किया जाता है।

रांची रेल मंडल ने गरीबों को भोजन कराया

रांची : रेलमंडल रांची द्वारा विभिन्न स्थानों पर 800 गरीब तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन का वितरण किया गया । रेल सुरक्षाबल रांची पोस्ट तथा आईआरसीटीसी द्वारा कृष्णापुरी एवं चुटिया में गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन का वितरण किया गया।

रेल सुरक्षाबल, हटिया पोस्ट, तथा आईआरसीटीसी द्वारा हटिया स्टेशनरोड, चाईबासा मुहल्ला, नीचे हटिया, जोजोबासा, चांदनी चौक एवं गणेश मुहल्ला में गरीब तथा जरूरत मंद व्यक्तियों को भोजन का वितरण किया गया।

अब लॉकडाउन से प्यार होने लगा है

अवनिश

आज इस चाइनीज वायरस के कहर से सारी दुनिया परेशान है। इटली और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और स्पेन जैसे विकसित देश हों या भारत जैसा विकासशील देश। सभी देश कोरोना से दहशत में हैं। गांव से लेकर शहरों तक को लॉकडाउन कर दिया गया है, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके।

आबादी का घर से निकलना बंद हो गया है। फैक्ट्रियों से धुआं निकलना बंद है। सड़कों पर गाड़ियों का चलना बंद है। कोरोना की वजह से देश और दुनिया की रफ्तार पर लगी ये इमर्जेंसी ब्रेक देशों को आर्थिक तौर पर भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है। निःसन्देह ये चिंताजनक है। मगर इसके विपरीत लॉकडाउन का एक दूसरा पहलू बहुत खुशनुमा और सकारात्मक भी है।

मुझे लगता है कि, अगर चीन ने दुनियां को कोरोना वायरस दिया तो प्रकृति ने लॉकडाउन के रूप में दुनियां को एक बहु-आयामी और सशक्त मार्ग दिखाया है। इतने दिनों से लगातार लॉकडाउन में रहते हुए क्या आपने कभी गौर किया कि, कोरोना की वजह से हुए इस लॉकडाउन ने दुनियाँ को क्या अच्छा दिया है?आईये देखते हैं लॉकडाउन ने हमें क्या क्या सौगात दिए?

लॉकडाउन के कारण देश भर में जरूरी गाड़ियों के अलावा यातायात पर पूरी तरह ब्रेक लगा। इसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में भारी गिरावट आई। सामान्यतः जहां रोज सैकड़ों रोड ऐक्सिडेंट की खबरें आती थीं और इनमें से कईयों की मौत हो जाती थी, अब ये संख्या ना के बराबर है। रोडरेज की घटनाएं भी बिल्कुल खत्म हो चलीं हैं।

लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां भी बंद पड़ी हैं। फैक्ट्रियों के कचरे और जहरीले रसायन भी इस समय नदियों में नहीं गिर रहे हैं। लोगों का नदियों के किनारे जाना भी बहुत हद तक बंद है जिसकी वजह प्लास्टिक व अन्य कचरों में भारी कमी आई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति स्वयं इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। तभी तो लॉकडाउन के बाद नदियों का पानी इतना साफ और स्वच्छ हो गया है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी। देश की लगभग सभी नदियों का यही हाल है। सभी नदियाँ पहले की तुलना में ज्यादा साफ और स्वच्छ हो गई हैं।

लुप्त हो चुके पक्षी कितने स्थानों पर अब वापस आसमान में उड़ते नज़र आने लगे हैं। कहीं शहर के आवासीय सोसाइटियों में मोर घूमने लगे हैं, तो कहीं हिरण सड़कों पे विचरण करते देखे जा रहे हैं। हरिद्वार और बनारस में गंगा का पानी अविश्वसनीय रूप से पारदर्शी और स्वच्छ हो चुका है। गंगा की लहरों पर अब राजहंसों ने अपना दावा फिर से ठोक दिया है।

पंजाब में जालंधर और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से हिमालय की श्रृंखलाओं का नज़ार आना अपने आप में एक अद्भत और अविस्मरणीय अनुभव है। जरा सोचिए,इस लॉकडाउन ने पर्यावरण को कितना स्वच्छ, कितना शुद्ध कर किया है। दिल्ली जैसे शहर में जो काम वर्षों से ड्रॉ-फिट चला कर केजरीवाल सरकार नहीं कर सकी, वो इस लॉकडाउन ने 10वें दिन से ही करना शुरू कर दिया।

10 लाख वर्ग किलोमीटर के घेरे में ओज़ोन की सतह पर बना वो छेद, जिसकी वजह से दुनिया भर के पर्यावरणविद और वैज्ञानिक दशकों से परेशान थे, आज लगभग भर गया है, जिसका हमारी पृथ्वी के वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है।

अगर लॉकडाउन के प्रभावों के पारिवारिक दृष्टिकोण पर नज़र डालें, तो हम देखेंगे कि, जिन पारिवारिक मूल्यों को हम भूल चुके थे, आज फिर से उन्होंने हमें अपनी सार्थकता का एहसास कराया। परिवार एक-जुट हो रहा है। संताने माता-पिता को वक्त दे रही हैं, उनका खयाल रखने की कोशिश कर रही हैं। कई परिवारों में सांझा चूल्हा फिर से जलने लगा है बच्चे फिर से नानी-दादी की कहानियाँ सुनने लगे हैं। रामायण और महाभारत के पात्र आज की पीढ़ी को भारतवर्ष की हमारी गौरवशाली सभ्यता और सांस्कृतिक मर्यादाओं का बोध करा रहे हैं। भारतीय समाज सदियों से जिस सांस्कृतिक धरोहर को भुला कर पश्चिमी संस्कृति की तरफ तेजी से भागने लगा था, आज पूरा विश्व हमारी उसी वैदिक संस्कृति की महत्ता को समझने लगा है। हाँ ! आज विश्व हमारे नमस्ते के विज्ञान को समझ रहा है। आज हमारी पीढ़ी को भी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं पर पुनः गर्वान्वित होने का मौका मिला है। सदियों से ये सब बस किसी सपने जैसा था, और आज हम उस सपने को जी रहे हैं।

अगर हम इस लॉकडाउन से पड़ने वाले प्रभावों को दूसरे नज़रिये से देखें तो हम पाएंगे कि, लॉकडाउन में जिसने जो भी खोया हो, उससे कहीं ज्यादा इस मानव सभ्यता को मिला है। लॉकडाउन ने जो दिया है वो मेरी समझ से इतना अनमोल है जिसे देशों की अर्थव्यवस्थाएँ कभी खरीद नहीं सकतीं। कई बार मुझे लगता है जैसे मुझे इस लॉकडाउन से प्यार होने लगा है ।बस अब हमें अपने जीवन में इन अनमोल धरोहरों के महत्व को पहचानते हुए इनको सम्भाल कर रखना है।

मेरा तो विचार है, कि सभी देशों की सरकारों को इस विषय पर एक राय बनानी चाहिए कि क्या हम कुछ दिनों के निश्चित अंतराल पर इस तरह के लॉकडाउन की एक स्थायी व्यवस्था कर सकते हैं, जो भविष्य में भी निरन्तर चलती रहे। आज के परिवेश में हमारी पृथ्वी के लिए ये लॉकडाउन निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। मुझे लगता है, प्रकृति ने ही हमें चेतावनी देते हुए प्रकृति को संवारने और संभालने के लिए लॉकडाउन का ये रास्ता दिखाया है।

आप क्या कहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि, lockdown को स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू करना चाहिए जो कुछ दिनों या महीनों में एक बार एक दिन के लिए ही सही पर चलती रहे?

बिरसा हरित ग्राम योजना आमदनी में होगा सहायक

रांची :मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ताकि उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। योजना के जरिये सरकार सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरुआ भूमि पर फलदार पौधा लगाया जाएगा। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी ग्रामीणों की होगी। उन्हें पौधा का पट्टा भी दिया जाएगा, जिससे वे फलों से आमदनी कर सकें। पौधारोपण के करीब तीन वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये की वार्षिक आमदनी होने की संभावना है। साथ ही फलों की उत्पादकता बढ़ने की स्थिति में फलों को

फोटो न्यूज

लॉकडाउन में मनुष्यों का निकलना कम हुआ तो सड़क पर हिरणों ने अपना आरामगाह बना लिया। तस्वीर भारत की नहीं विदेश के किसी शहर की है

ऐसे रखें दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ मजबूत

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

खुबसूरत ,सफेद और स्वस्थ्य दांत आपकी सुन्दरता में चार चांद लगा देते हैं परन्तु आज- कल दांतों की समस्या काफी बढ़ गई है। बाकी बीमारियों की तरह ही दांतों की समस्या आम हो गयी है, जैसे कैविटी , मसूड़ों से खून आना, दांतों में दर्द , मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों में सुजन होना, दांतों का पीलापन आदि। हम अपने दांतों को हमेशा ही नजरअंदाज करते हैं। हमारे दांत दिनभर काम करते हैं और सिर्फ एक बार ही ब्रश करना काफी नहीं होता। हमें इनकी याद उस वक्त आती है जब ये बुरी तरह से खराब हो जाते हैं या फिर काफी दर्द शुरू हो जाता है और फिर हम डेंटिस्ट के पास भागते हैं। इसमें एक तो काफी पैसे खर्च हो जाते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान दर्द भी काफी सहना पड़ता है। दांतों की देखभाल के लिए हमें कुछ सामान्य सावधानियां रखनी चाहिए।

●हमें खाना खाने के बाद साफ पानी से कुल्ला करने की आदत डालनी चाहिए। इससे दांतों के बीच में जो भी खाना फंसा होगा वो निकल जायेगा क्योंकि दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना सड़ जाता है और फिर बाद में कैविटी आदि समस्या हो जाती है। पानी एक नैचुरल माउथवॉश के जैसे काम करता है।

●खाद्य पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक,मैदा के बने पदार्थ,सोडा ,कोला का सेवन दांतों को हानि पहुंचाता है इनका सेवन करते हैं तो बाद में कुल्ला करना न भूलें।

●दांतों को पिन ,सुई , किसी अन्य नुकीली चीज से न कुरेदे। ये हमारे मसूड़ों में घाव कर सकता है।

●धूम्रपान , तंबाकू,पान आदि दांतों को गंदा और साथ ही साथ कमजोर बनातें है , इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए।

●दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए जैसे जीने के लिए दो वक्त की रोटी चाहिए वैसे ही दांतों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए उन्हें सुबह के साथ -साथ रात को सोते समय भी एक बार ब्रश करना चाहिए।

●समय-समय पर अपने ब्रश को बदलते रहना चाहिए और अच्छे क्वालिटी का ब्रश ही इस्तेमाल करना चाहिए।

● जितना हो सके फलों और सब्जियों को चबाकर खाना चाहिए इससे दांतों का एक्साइज तो होता ही है साथ में इसे जरूरी इंन्जाइमस भी मिलते हैं।

●समय-समय पर डेंटिस्ट से दांतों की जांच करानी चाहिए। वर्ष में दो बार ,अगर दो बार सम्भव न हो तो कम से कम एक बार जांच जरूरी करानी चाहिए।

● दांतों के साथ-साथ जीभ की भी सफाई जरूरी है । इसकी सफाई के लिए टंग क्लीनर या ब्रश के पीछे वाले हिस्से का इस्तेमाल करें।

● फ्लॉस (दांत साफ करने वाला धागा) इसके इस्तेमाल से हम दांतों के बीच में फंसा हुआ खाद्य-पदार्थ निकाल सकते हैं।

● ऑयल पुलिंग थैरेपी भी काफी मददगार है। सुबह-सुबह खाली पेट कोई भी तेल जैसे नारियल, सीसम आदि खाली पेट मुंह में 20 मिनट तक रखे फिर कुल्ला कर लें। इससे दांत और मसूड़े दोनों ही स्वस्थ और मजबूत बनते हैं।

अगर हमें स्वस्थ , मजबूत और चमकदार दांत चाहिए तो इन कुछ छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना होगा ।

चारे के जुगाड़ में स्वर्णरिखा नदी की सफाई हो गयी

पहले

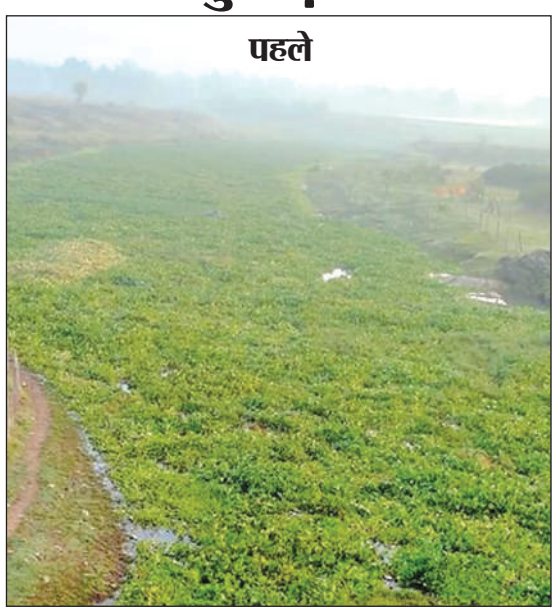

बाद में

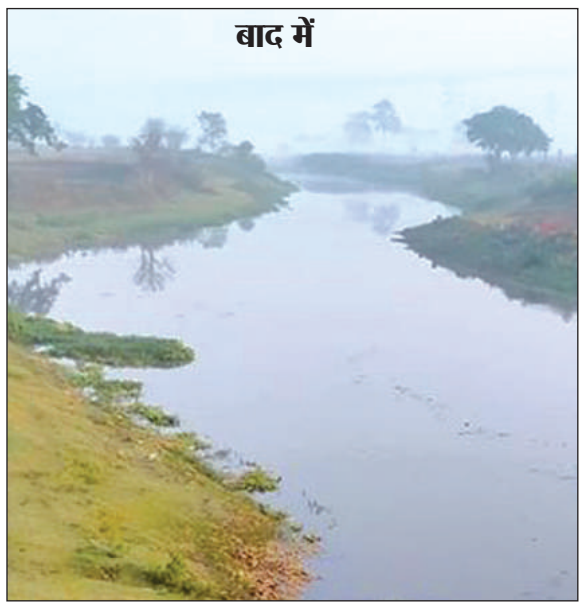

तस्वीर सतीश जी के फेसबुक वाल से है: उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में सुअरों के लिये चारे की कमी होने पर पशुपालकों ने स्वर्णरिखा नदी से शैवाल निकाल कर सुअरों को खिलाना शुरू कर दिया और इस चक्कर में नदी की सफाई हो गयी

उपहास का पात्र नहीं औषधीय पौधा है पुदीना

देवाशीष

अक्सर डिंग हांकने वाले को उपहास में कहा जाता है कि उसने तो बावन बीघे में सिर्फ पुदीना ही लगा रखा है। यहां कहावत में पुदीने को तुच्छ और बेकार चीज माना गया है। हकीकत में पुदीना एक खाने योग्य और औषधीय पौधा है। इसके महक और गुणों के कारण इससे दवाइयां बनती हैं और इसके इसेंस का उपयोग खाने वाली चीजों में होता है। इसी कारण से कुछ जगहों पर इसकी व्यावसायिक खेती भी होती है। गांव देहातों में तो यह स्वत: ही जहां तहां उग आते हैं।

संस्कृत में पुदीने को पुतिहा कहा गया है अर्थात दुर्गंध का नाश करने वाला। पुदीना का स्वाद और सुगन्ध दोनो लाजवाब है वही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण। पुदीने को शाखा कलम व जड़,दोनो प्रकार से लगाया जा सकता हैं। पुदीने की पत्तियों को मुख्य रूप से चटनी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चटपटी चटनी खाने के स्वाद को दोगुना कर देती है। पुदीना मुख्य आहार तो नहीं है लेकिन इसकी मौजूदगी से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। पुदीने का उपयोग दवाइयों में,सौंदर्य प्रसाधनों, च्यूंगम, टूथपेस्ट, पेय प्रदार्थो,सिगरेट,पानमसाला आदि में सुंगन्ध बढ़ाने के रूप में किया जाता हैं। अमृतधारा औषधि में भी सतपुदिने का उपयोग किया जाता है। राजस्थान वगैरह में पुदीने की चाय भी पी जाती है। हाजमे के लिए ये एक अचूक उपाय है। इसके सेवन से पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो पुदीने की कुछ पत्तियों को चबा लें, इसके पानी से कुल्ला करने पर भी बदबू चली जाएगी पुदीना त्वचा से जुड़ी कई बीमारियों में भी एक अचूक उपचार है। गर्मी में लू से बचने के लिए भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है इसके रस को पीकर बाहर निकलने से धूप लगने का डर भी कम रहता है।

हैजा होने पर पुदीना, प्याज का रस, नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से फायदा होगा। उल्टी होने पर आधा कप पुदीना का रस पीने से उल्टी आना बंद हो जाएगी पेट दर्द होने पर भी पुदीने को जीरा, काली मिर्च और हींग के साथ मिलाकर खाने से आराम होता है पुदीने की ताजी पत्तियों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे को ठंडक मिलती है।

सेंधा नमक यानि सैंधव नमक की कहानी

सेंधा नमक बनता नहीं है पहले से ही बना बनाया है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को 'सेंधा नमक' या 'सैन्धव नमक', लाहोरी नमक आदि आदि नाम से जाना जाता है। जिसका मतलब है 'सिंध या सिन्धु के इलाक़े से आया हुआ वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ है सुरंगे है। वहाँ से ये नमक आता है ,मोटे मोटे टुकड़ो मे होता है आजकल पीसा हुआ भी आने लगा है।

ये प्राकृतिक रूप में प्राप्य है और गुणकारी है, इसे शुद्ध माना गया है इसी कारण से उपवास ,व्रत मे सब सेंधा नमक ही खाते हैं। वहीं हम जो नमक खाते हैं उसमें कोंइ तत्व नहीं होता। आयोडीन और फ्रीफ्लो नमक बनाते समय नमक से सारे तत्व निकाल लिए जाते हैं और उनकी बिक्री अलग से करके बाजार में सिर्फ सोडियम वाला नमक ही उपलब्ध होता है जो आयोडीन की कमी के नाम पर पूरे देश में बेचा जाता है, जबकि आयोडीन की कमी सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाइ जाती है इसलिए आयोडीन युक्त नमक केवल उन्ही क्षेत्रों के लिए जरुरी है।

भारत मे 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था सब सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियों पर नियन्त्रण रहता है। क्योंकि ये अम्लीय नहीं ये क्षारीय है। क्षारीय चीज जब अमल मे मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है ।और रक्त अमलता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं ये नामक शरीर मे पूरी तरह से घुलनशील है ।सेंधा नमक शरीर मे 97 पोषक तत्वो की कमी को पूरा करता है ।

ऑनलाइन पढाई जरूरी नहीं एक मजबूरी है

शशिभूषण

तकनीक के युग में ऑनलाइन पढाई कोई नयी चीज नहीं है, लेकिन आज लॉकडाउन में ये स्कूली बच्चों के लिये मजबूरी है जरूरी कतई नहीं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कक्षा में शिक्षकों से सामने की पढाई में, अपने सहपाठियों मित्रों के साथ बातचीत और चर्चा करने से कई चीजों को सीखते हैं। लेकिन ऑनलाइन कक्षायें उन्हें एक-ाकी बना देंगी और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिये भी ये सही नहीं। इसलिये भविष्य में भी स्कूली पढाई के लिये ये कोई कारगर माध्यम नहीं।

आज लॉकडाउन में जिस तरह से शहर में स्कूलों की क्लासें ऑनलाइन चल रही है इससे एक बात तो स्पष्ट है की संसाधन से ही सब चीजें सार्थक होगी वही दूसरी ओर गांव या कस्बों में रहने वाले गरीब बच्चों की दशा उतनी बेहतर नहीं कि वो ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़ सके, क्योंकि इसके लिए स्मार्टफ़ोन की आवश्यकता है। इस विषम परिस्थिति में उनके सामने पहले अपने भोजन की चिंता ही सबसे बड़ी है । हालांकि गांव में भी लगभग हर घर में मोबाइल है लेकिन 80 फीसदी लोगों के पास एंड्राइड फोन नहीं है,जिससे उनके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। रांची के बेडो में ग्रामीण स्तर पर संचालित होने वाले विद्यालय रामकृष्ण विद्यानिकेतन की प्राचार्या विनीता कुमारी से जब इस बारे में बात की गयी तो वो कहती हैं कि हमारे यहां करीब 150 बच्चें है ,जिसमे हमलोग भी अपने स्तर से कोशिश किये तो करीब 20 से 30 बच्चों के पास ही एंड्राइड सेट है जो की अलग-अलग कक्षाओं में पढने वाले हैं ,अब इसके लिए थोड़े बच्चों को भी इस ऑनलाइन की सुविधा में जोड़ना बहुत मुश्किल है,इसलिए अभी फिलहाल हमलोग ऊपर के एक कक्षा में जिसमे सभी आस पास रहने वाले एक ही बस्ती के है, उनमें से दो या तीन बच्चें शामिल होते है उन्ही का बस क्लास ले पा रहे हैं। ये समस्या लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई है हालांकि इनके अभिभावकों को सबसे बड़ी चिंता भी हो रही है की कब तक लॉक डाउन रहेगा और उनके पास अपनी अशिक्षा की वजह से भी खुद को कोस रहे है कि आखिर करे भी तो क्या करे । ग्रामीण स्तर पर लोगों का मोबाइल उपयोग करना मनोरंजन के लिये उसे चलाना अलग विषय है, पर शिक्षा के लिये इसका उपयोग मुश्किल है। वही दूसरी ओर शहरी स्तर पर पढने वाले जो विद्यार्थी है उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि स्कूल कब से खुलेंगे ऑनलाइन क्लासेज देकर बच्चों को नये सिलेबस से पढ़ाना स्कूलों ने शुरू कर दिया है। कई स्कूलों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेज में जो सिलेबस कराया गया है वो बाद में नहीं दोहराया जाएगा। कक्षाएं सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है जो दो से चार घंटे तक चलती हैं। इस मसले पर सुरेन्द्र नाथ सेंटेनरी की 9 वीं कक्षा में पढने वाले एक छात्र के अभिभावक ने बताया की सारा क्लास वाट्सेप पर हीं हो रहा है इससे बच्चे सीखते हैं और व्यस्त भी रहते है लेकिन इसमें बच्चें पहले से कहीं ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं, अब उनको चिंता सता रही है किइसके अलावे टीवी पर भी देखने में टाइम देते हैं तो उनका आंख पर ज्यादा जोर न पड़े।

केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान के डॉ निशांत गोयल बताते हैं कि बच्चों के लिए जो समय बर्बाद होगा इसलिए इस समय में ऑनलाइन क्लासेस अच्छा माध्यम है लेकिन उन अभिभावकों को ध्यान रखने की सलाह भी दी है की बच्चें अपना स्क्रीन टाइम लिमिट में यूज करें यदि ऐसा नहीं करते है तो उनमे शारीरिक और मानसिक असर पड़ सकता है।

क्या होता है स्क्रीन टाइम ?

स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि बच्चा 24 घंटा में कितने घंटे मोबाइल टीवी लैपटॉप और टैबलेट जैसे गैजेट का इस्तेमाल करता है। 18 महीने से कम उम्र के बच्चे स्क्रीन का इस्तेमाल न करें। 18 से 24 महीने के बच्चे को माता पिता उच्च गुणवत्ता वाले प्रोग्राम ही दिखाएं। दो से पांच साल के बच्चे एक घंटे से ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल न करें।

कोविड-19 के बाद की दुनिया होगी बिल्कुल अलग

सुनीता नारायण

कोविड-19 हमारे जीवनकाल की सर्वाधिक उथल-पुथल भरी, सर्वाधिक विनाशकारी और सबसे ज्यादा निर्धारक परिघटना है। मैं दूसरी किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती जो इतने कम समय में इस तरह फैली हो।

गत दिसंबर में कोरोना बीमारी का पहला मामला चीन में आया था और अप्रैल के मध्य तक पूरी दुनिया की एक-तिहाई आबादी अपने घरों में कैद हो चुकी है। ऐसे संकट की कोई भी नजीर नहीं है जो सरकारों को बता सके कि उन्हें क्या करना है, अर्थव्यवस्थाओं को किस तरह बंद करना है और कब उन्हें दोबारा खोलना है? यह वायरस उत्परिवर्तन से उपजा है जो जानवर से इंसानों तक आया, यह खुद को छिपाने के नए तरीके ईजाद करने में सफल होने से घातक है। शरीर में लक्षण न दिखने पर भी हम इस वायरस के संवाहक हो सकते हैं।लेकिन हमें अपनी दुनिया की सामूहिक कमजोरी के बारे में सोचना चाहिए। सर्वाधिक रसूखदार नेता, सर्वाधिक उन्नत वैज्ञानिक प्रतिष्ठान और सबसे ताकतवर आर्थिक शक्तियों को इस तुच्छ वायरस के रूप में तगड़ी चुनौती मिली है। इस स्थिति में हमें विनम्रता के साथ सोचना चाहिए कि क्या अलग करने की जरूरत है, हमें किस तरह से काम करने और व्यवहार करने की जरूरत है? लेकिन मुझे शक है कि हम इस बारे में गलती करेंगे।जब भी कोई विनाशकारी घटना होती है तो ध्यान तात्कालिक राहत एवं बचाव कार्यों पर होता है, न कि इस पर कि इससे भविष्य के लिए क्या सीख सकते हैं? कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की अनिवार्यताएं बेहद तात्कालिक एवं अपरिहार्य किस्म की हैं। अस्पतालों एवं स्वास्थ्य देखभाल की समुचित व्यवस्था वाले संपन्न देशों में भी महामारी के चलते हजारों लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में विकासशील देशों में इस मानव त्रासदी की गंभीरता का अंदाजा लगाइए जहां ये सुविधाएं नगण्य हैं। महामारी के चलते गरीबों को बड़ी संख्या में अपना काम-धंधा गंवाना पड़ा है, उनकी आर्थिक स्थिति रोजगार की सुरक्षा पर नहीं बल्कि रोज की कमाई पर निर्भर होती है।लेकिन कोविड-19 का प्रकोप खत्म होने के बाद भी जिंदगी होगी। सवाल है कि नई सामान्य स्थिति क्या होगी? चलिए, अपने वैश्वीकृत विश्व के सबसे अहम मुद्दे के बारे में चर्चा करते है: अगली आपातस्थिति आने से निपटने के लिए हमारे नेताओं एवं संस्थानों को इस महामारी से क्या सीखना होगा? कड़वा सच तो यह है कि मिलकर काम करने की अहमियत पता होते हुए भी हमने ऐसा नहीं किया।

चीन ने कोरोनावायरस के बारे में बाकी दुनिया को जल्द जानकारी नहीं दी जिससे वायरस चीन से बाहर फैला और संक्रमण बढ़ता गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पर्याप्त तेजी नहीं दिखाई या शायद उसकी बात को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। जनवरी के अंत तक डब्ल्यूएचओ वायरस के चीन तक ही सीमित रखने के दावे कर रहा था, यहां तक कि उसने कुछ देशों द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों का विरोध भी किया था और इस संकट को महामारी घोषित करने में भी आनाकानी की। जब इसने कदम उठाए तब भी इसने स्वास्थ्य आपातकाल की गंभीरता के हिसाब से काम नहीं किया। इस संकट काल में डब्ल्यूएचओ ने विश्वसनीयता गंवा दी है । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ऐसे समय में भी कई हफ्तों तक बैठक नहीं हुई और जब हुई तो भी यह बच्चे के रुदन जैसा ही था। हरेक देश ने यही दिखाया है कि वह इस संकट के समय में केवल अपने बारे में सोच रहा है। हालत ऐसी है कि देश स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जरूरी सुरक्षात्मक पोशाक पीपीई और मास्क के लिए डाका डालने लगे हैं, दवाओं की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं और इस जानलेवा बीमारी की पहली वैक्सीन बनाने की होड़ में लगे हैं।, ऐसे में तमाम देशों के मौजूदा रुख काफी डराते हैं। सच है कि यह वायरस चीन के एक ऐसे प्रांत से निकला है जिसके निवासियों का खानपान के साथ मनहूस रिश्ता जगजाहिर है। लेकिन संक्रमण दुनिया भर में इसलिए फैला कि हम एक अंतर-संबद्ध दुनिया में रहते हैं। यह भी स्पष्ट है कि हम अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितने ही मजबूत होते हैं। अगर वायरस का प्रसार जारी रहता है तो सबसे कमजोर स्वास्थ्य सेवा वाले या युद्ध एवं संकट से बेहाल किसी देश में यह वायरस बना रहेगा। हम इस जंग को एक साथ होने पर ही जीत पाएंगे। यही वजह है कि मौजूदा वैश्विक नेतृत्व की शोचनीय हालत को लेकर हमें फिक्रमंद होना चाहिए।

कई लोगों का कहना है कि कोविड-19 बहुपक्षीयता के अंत, संयुक्त राष्ट्र और उसके बुनियादी सिद्धांतों का खात्मा लेकर आया है। लेकिन कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन के रूप में आसन्न वैश्विक आपातस्थिति में एकपक्षीयता काम नहीं करेगी। कोविड-19 की ही तरह जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए भी वैश्विक नेतृत्व की जरूरत है। अगर एक देश भी उत्सर्जन जारी रखता है तो बाकी देशों के सारे प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सभी देश खुलकर इस कोशिश में शामिल हों तो फिर हमें एक सहकारी समझौता तैयार करना होगा जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति, दुनिया के अंतिम देश के पास भी विकास का अधिकार हो। हमें एक वैश्वीकृत अंतर्निर्भर विश्व में वैश्विक नेतृत्व की जरूरत है। लिहाजा, कोविड-19 के बाद की दुनिया की नई सामान्य स्थिति में हमें इस बात को याद रखना होगा। हम इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं, यह आने वाले कल का सवाल है लेकिन हमें यह करना ही होगा।

गंगा यमुना के प्रदूषण का मुख्य कारण सीवेज हैं

एजेंसियां : गंगा और यमुनानदी को प्रदूषित करने में घरेलू सीवेज ही मुख्य कारण है। नदी के किनारे स्थित 50 शहरों के जरिए हर दिन लगभग 2,723-30 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उत्सर्जित किया जाता है। सीपीसीबी द्वारा रखी गई निगरानी के आधार पर तैयार किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि गंगा के किनारे 36 निगरानी इकाइयों में से 27 में स्नान के लिए पानी सही था। डेटा में पाया गया कि पानी कुछ स्थानों पर पीने के लिए भी उपयुक्त था, जहां जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग (बीओडी) तीन मिलीग्राम प्रति लीटर मिलीग्राम से कम था, हालांकि सीपीसीबी के वास्तविक समय के आंकड़ों की अपनी सीमाएं हैं और पूरी तस्वीर नहीं दे सकती है।

वहीं दिल्ली में यमुना के बारे में लौकडाउन के दरम्यान जो प्रदूषण कम होने का दावा किया जा रहा है वह भ्रामक है। लौक-डाउन से पानी साफ हुआ है पर ऐसा भी नहीं कि यमुना बिल्कुल स्वच्छता की ओर है।अभी सिर्फ उद्योगों के कचरे का आना बंद है यमुना में घरेलु सीवेज का बहना बंद नहीं हुआ है जो मुख्य रूप से प्रदूषण का कारक है

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादक: एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।